IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में कृषि–बेरोज़गारी की समस्या

डॉ मनोज कुमार सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास), अनुपमा सिंह (शोध छात्रा), इतिहास–विभाग राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ जौनपुर।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेरोज़गारी एक गम्भीर समस्या है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए इस समस्या से निपटना अपने आप में अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है जहाँ देश की आबादी अत्यंत ही विशाल है। भारत की आधी से अधिक आबादी किसी न किसी रूप में चाहे मालिकाना रूप से या श्रमिक के तौर पर कृषि–कार्य में संलग्न है। कृषि–क्षेत्र ने हमेशा से अपनी सार्थकता सिद्ध की है। स्वतंत्रता के बाद जब भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था तब कृषि–क्षेत्र मात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने भारत को न केवल अपने पैरों पर खड़ा किया अपितु वर्तमान समय में कोरोनाकाल जैसी आपातकालीन परिस्थिति में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को सँभाले रखा है।

आज़ादी के बाद भारत कृषि में आत्मनिर्भर होने के साथ खाद्यान्नों के निर्यातक देशों की सूची में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। पारम्परिक रूप से कृषि–क्षेत्र रोज़गार का प्रमुख स्रोत रहा है और इसी के चलते प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि– क्षेत्र के चतुर्दिक विकास को प्राथमिकता प्रदान की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप एक समय भारत की अर्थव्यवस्था की GDP में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का योगदान 51.81 प्रतिशत तक हो गया था। परंतु जैसे–जैसे देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती गयी एवं अर्थव्यवस्था में नवीन क्षेत्रों का विस्तार होता गया, भारत की GDP में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की भूमिका कम होती गयी और इसका योगदान 2020–21 तक घटकर 20.19 प्रतिशत हो गया। निम्न चित्र में इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है :

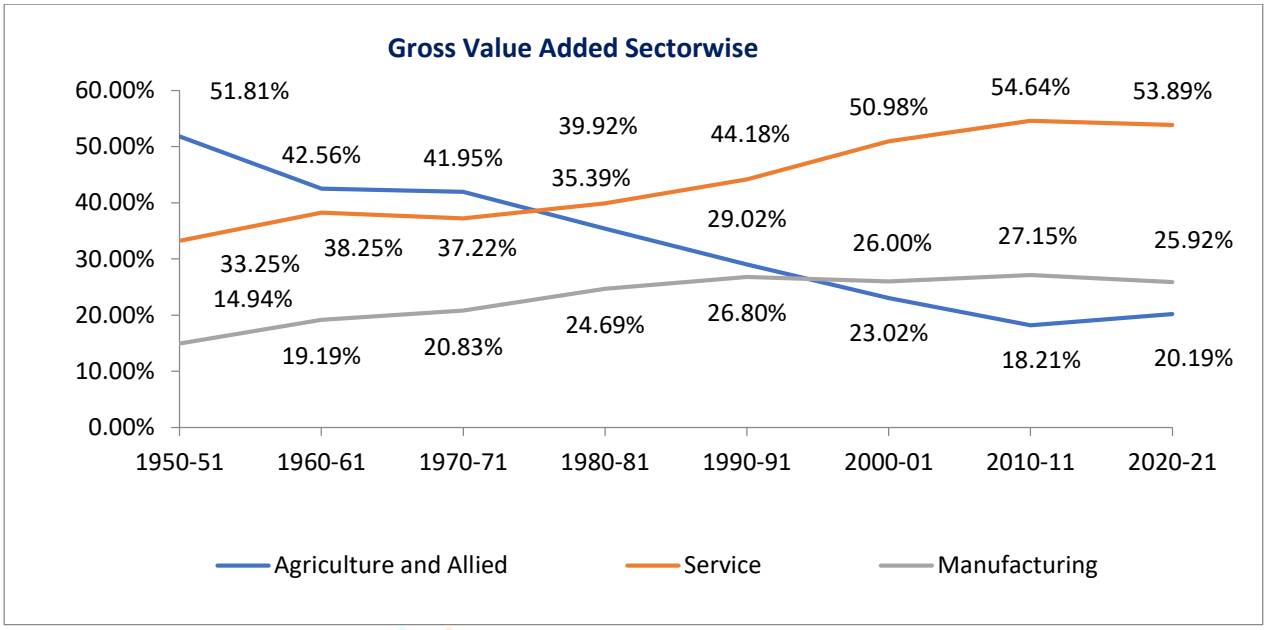

Figure 1: Gross Value added sector wise in India

Source: https://statisticstimes.com

1980 के समय तक भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि-कार्य में संलग्न थी और 2020 तक आते-आते इसका ग्राफ़ गिरकर 55 प्रतिशत पहुँच गया है। कृषि-क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या की दर गिरने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की GDP में भी कृषि-क्षेत्र की भागेदारी में भारी गिरावट आयी जो कि 1980 में 39 प्रतिशत थी और 2020 तक घटकर 20 प्रतिशत हो गयी। नीचे दिए चित्र में यह अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है:

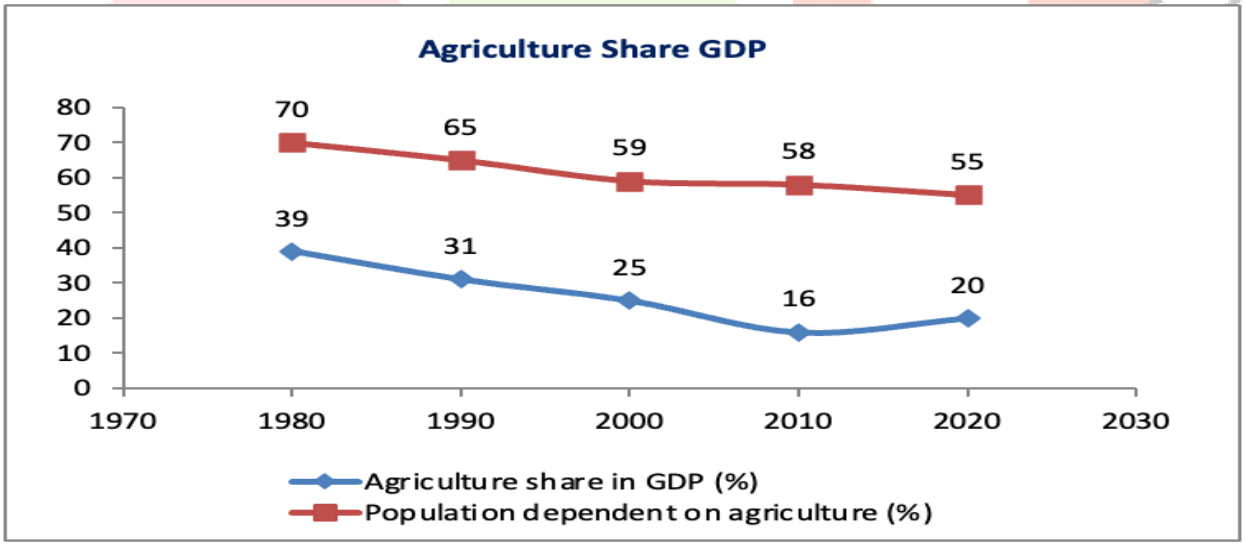

Figure2: Agriculture share in India GDP vis-à-vis population dependent

इन आकड़ों से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि-क्षेत्र का योगदान पहले से कम हुआ है हालाँकि कृषि-क्षेत्र में संलग्न लोगों की सालाना आय में बढ़ोत्तरी हुई है जो नीचे दिए गए ग्राफ़ से स्पष्ट है:

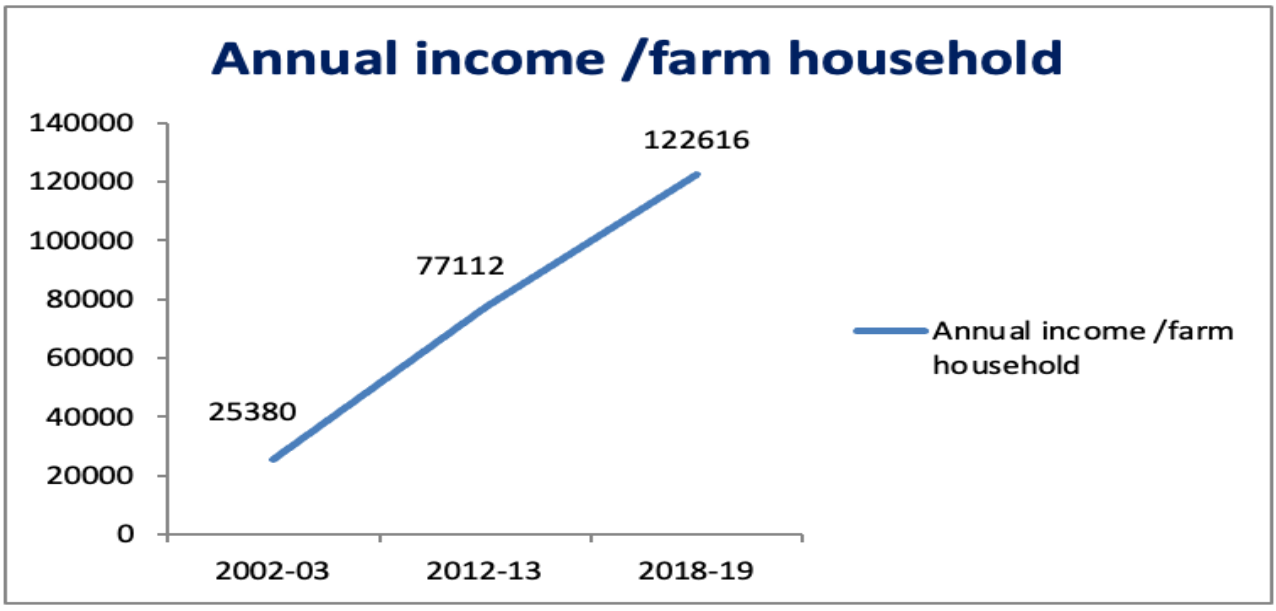

Figure 3: Average Annual Income per farm household in India
Source: https://www.thehindubusinessline.com

कृषि-कार्य में आय का बढ़ना यद्यपि अच्छा संकेत है किन्तु प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी का एक प्रमुख कारण कृषि-क्षेत्र पर निर्भर लोगों की संख्या में गिरावट होना है और इस गिरावट का मुख्य कारण कृषि-क्षेत्र में विद्यमान प्रछन्न बेरोज़गारी के चलते लोगों का अन्य क्षेत्रों में रोज़गार की तलाश में पलायन कर जाना है।

भारत में कृषि-बेरोज़गारी का स्वरूप अलग-अलग है। परंतु इसमें सबसे बड़ी चुनौती कृषि में अदृश्य या प्रछन्न बेरोज़गारी (Disguised Unemployment) की है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इसमें संलग्न है लेकिन उसका योगदान न के बराबर है। अगर उसको वहाँ से हटा दिया जाये तो उसका उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ प्रछन्न बेरोज़गारी की बात कर रहे तो इस समस्या को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है और इससे निपटना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि समय-समय पर सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएँ चलाकर इसे दूर करने का प्रयास किया गया जिसमें **मनरेगा** (MNREGA) सरकार द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी क़दम है। परंतु केवल सीमित प्रयासों से कृषि-बेरोज़गारी को दूर नहीं किया जा सकता है बल्कि कृषि-क्षेत्रों को विशेष महत्त्व देने की आवश्यकता है और इसके लिए सर्वप्रथम कृषि से लोगों के पलायन को रोकना अत्यंत आवश्यक है।

प्राचीन काल से भारतीय किसान परम्परागत तरीक़ों से खेती करके अपनी आजीविका की पूर्ति करता आया है परंतु वर्तमान समय में खेती करने के तरीक़ों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। दिन-प्रतिदिन बढ़ती बेरोज़गारी ने लोगों की समस्याओं को अधिक बढ़ा दिया है। कृषि-क्षेत्र हमेशा से रोज़गार का स्रोत रहा है इसलिए इसकी अनदेखी न करके कृषि-क्षेत्र को अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। **ऐसे में कृषि-विविधीकरण ग्रामीण रोज़गार का एक बेहतर विकल्प हो सकता है।** इसके अंतर्गत विभिन्न कृषिगत गतिविधियों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, सुअर पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा देकर लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने चाहिए। यद्यपि ऐसे कार्यों में पहले से ही अधिकांश जनसंख्या संलग्न है फिर भी इसमें और अधिक सुधार एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। **कृषि-विविधीकरण कृषि में टिकाऊ उत्पादन, स्थायी आमदनी और रोज़गार में स्थायित्त्व प्रदान करने के साथ प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न जोखिमों को भी कम करता है।** इसका उदाहरण वर्ष 2020 में देखा जा चुका है जब कोविड-19 की समस्या से जूझते हुए विश्व के अनेक विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी थी उस समय भारतीय कृषि ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया अपितु उसके विकास की गति को भी बढ़ाने में भी सहायक रही।

भारत में कृषि-क्षेत्र में विद्यमान प्रछन्न बेरोज़गारी की जो गम्भीर समस्या है उसके लिए **कृषि-विविधीकरण** एक बेहतर विकल्प हो सकता है। जहाँ एक ओर यह लोगों को रोज़गार के अवसर देगा वहीं दूसरी ओर कृषि से पलायन कर रहे लोगों को रोकने में भी सहायक होगा। भारत की जनसंख्या में वृद्धि होने से भी देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है। जिस दर से देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस दर से रोज़गार का सृजन नहीं हो रहा है और न ही कृषिगत भूमि की सीमा में वृद्धि हो रही है जिसके कारण भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है और प्रति व्यक्ति भूमि भी घटती जा रही है। इससे व्यक्तियों की उपयोगिता घट गयी है क्योंकि जिस कार्य को एक व्यक्ति कर सकता है उसमें एक से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। इस विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए कृषि-योग्य भूमि की सीमा को बढ़ाया जाना आवश्यक है। जो भूमि खेती करने योग्य नहीं है उसे खेती करने योग्य बनाया जाना चाहिए। बंजर भूमि को भी इस सीमा में लाकर कृषि-भूमि में विस्तार किया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-कार्य में संलग्न लोगों के लिए रोज़गार बढ़ने की सम्भावना के साथ कृषि से होने वाली आय में भी वृद्धि होगी।
भारत में खेतों के छोटे और छिटके होने के कारण कृषि-उत्पादकता घटने से होने वाली आय में कमी आती है और साथ ही बेरोज़गारी में भी वृद्धि होती है। इसके लिए कृषि-जोतों के आकार में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कृषि-उत्पादन को बढ़ाया जा सके और प्रछन्न बेरोज़गारी की समस्या से कारगर तरीक़े से निपटा जा सके।

भारतीय कृषि के मौसम पर आधारित होने के कारण इसमें श्रमिकों को वर्ष-पर्यंत रोज़गार की गारंटी नहीं रहती है। किसानों और श्रमिकों के पास केवल कुछ महीनों का ही काम रहता है। ख़ाली मौसम में उनके पास केवल कुछ घंटे का ही काम होता है जो कि एक विकट समस्या है। **आवश्यकता इस बात की है समय रहते इस पर उचित ध्यान दिया जाए और कृषकों एवं श्रमिकों को कृषि या उससे जुड़े क्षेत्रों में रोज़गार के विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराये जायें जिसके अंतर्गत कृषि-विविधीकरण और सहायक एवं अनुपूरक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।** कृषि-अर्थव्यवस्था में आंशिक बेरोज़गारी को दूर करने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास भी अपेक्षित है। **लघु एवं कुटीर उद्योग श्रम-गहन होते हैं क्योंकि वे बड़ी मात्रा में बेकार एवं अर्द्धबेकार श्रमिकों को रोज़गार प्रदान कर सकते हैं।** भारत की ग्रामीण जनता को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक है कि भारत में कृषि-आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास सुनिश्चित किया जाये।

भारत में कृषि का स्वरूप संगठित नहीं है और किसानों का कृषि करने का ढंग भी अवैज्ञानिक है। सभी किसानों में केवल बड़े किसान ही अधिक सम्पन्न हैं जिनके पास खेती करने के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। अधिकांश किसानों के पास कृषि के साधनों की कमी है। उत्तम बीज, खाद, उर्वरक एवं उन्नत यंत्रों के अभाव में भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है जिसके कारण कृषि-कार्य से होने वाली आय में कमी होने के कारण अधिक रोज़गार का सृजन नहीं हो पाता है।

कृषि और कृषिगत उद्योगों में बढ़ते यंत्रीकरण से एक ओर कृषि-उत्पादन में वृद्धि हो रही है वहीं दूसरी ओर यह प्रक्रिया बेरोज़गारी को जन्म दे रही है। **कृषि-यंत्रीकरण** में कम लोगों के माध्यम से ही काम हो जा रहा है जिससे कई लोग काम से वंचित हो जाते हैं और बेरोज़गार हो जाते हैं जिस पर विशेष ध्यान देकर होने वाली बेरोज़गारी को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

कृषि-बेरोज़गारी दूर करने के इन विभिन्न उपायों के साथ-साथ एक महत्त्वपूर्ण बिंदु **कृषि-शिक्षा** है जिसकी भारतीय किसानों तक पहुँच सुनिश्चित करना राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों का दायित्त्व है। **कृषि-शिक्षा** के अंतर्गत समय-समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को कृषि की नवीन पद्धतियों एवं तकनीकों के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि विगत कुछ वर्षों में भारत में कृषि-क्षेत्र में बेरोज़गारी की समस्या ने एक भयावह रूप धारण कर लिया है जिसका यदि समय से समुचित समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में यह सामाजिक एवं आर्थिक विघटन की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस सम्बंध में केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों को पारस्परिक सामंजस्य एवं सहयोग के माध्यम से कृषि-क्षेत्र में सुधारात्मक क़दम उठाये जाने की आवश्यकता है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि जनसांख्यिकीय संरचना के अनुसार भारत युवाओं का देश है जिसमें समस्त विश्व का 21 प्रतिशत युवा भारत में रहता है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान न खोजा गया और युवाओं को रोज़गार के समुचित अवसर नहीं उपलब्ध कराये जा सके तो हम अपनी विशाल युवा मानव-संसाधन का अनुकूलतम दोहन करने से वंचित रह जायेंगे। एक राष्ट्र के तौर पर यह हमारी ऐतिहासिक विफलता होगी क्योंकि रोज़गार के अवसर उपलब्ध न होने की स्थिति में युवा पीढ़ी के सम्मुख सामाजिक विघटन की सम्भावना हमेशा बनी रहेगी। **कृषि-क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग है या यूँ कहें कि कृषि-क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।** कृषि-क्षेत्र के विकास के अभाव में भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास की कल्पना करना बेमानी होगा। अतएव कृषि-क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ कृषिगत बेरोज़गारी को दूर किया जाना हमारी सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ-सूची

1. कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय
2. 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए कृषि का रूपांतरण-नीति आयोग की रिपोर्ट
3. *https://statisticstimes.com*
4. *https://www.thehindubusinessline.com*
5. योजना पत्रिका
6. कृषि जागरण पत्रिका

डॉ मनोज कुमार सिंह असिस्टेंट-प्रोफेसर (इतिहास), अनुपमा सिंह(शोध-छात्रा) इतिहास-विभाग, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय, सिंगरामऊ ,जौनपुर।